ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-8* November-2021
Anthology : The Research

वामपंथ की विभाजनकारी राजनीति
Left's Divisive Politics

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance:2311/2021, Date of Publication: 24/11/2021

गिरीश चन्द पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग
एस0 डी0 पी0 जी0 कालेज
मठ-लार, देवरिया,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

एक राष्ट्र के रुप में भारत के प्रति वामपंथियों का दृष्टिकोंण प्रारम्भ से ही नकारात्मक रहा है। इन्होंने कभी यह स्वीकार ही नही किया कि भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र है। अपनी इसी सोच के कारण मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के विभाजनकारी लाहौर प्रस्ताव का कम्युनिस्टों ने खुलकर समर्थन किया था। आज भी गोआ, मिजोरम, मणिपुर, कश्मीर और केरल आदि राज्यों के लिए आजादी की मांग करके वामपंथी अपने राष्ट्र विरोधी एजेण्डे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तव में वामपंथी विचारधारा हमेशा से ही विस्तारवाद की रही है। यह अपने विस्तार के मार्ग में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना को सबसे बड़ी बाधा मानते है। इसीलिए इस्लाम और ईसाईयत से इनके स्वाभाविक रिश्ते बन जाते हैं। इसी कारण वामपंथियों ने हमेशा से ही इस्लामी धर्मान्धता को धर्मनिरपेक्षता के आवरण में ढकने का प्रयास किया है। आज जब लगभग समूचा संसार और सभ्यता का जीवन जेहादी मानसिकता और मजहबी आतंकवाद से जुझ रहा है तब भी इनके बचाव में तर्क गढ़ने और आमजनमानस को दिग्भ्रमित करने का निर्लज्ज प्रयास वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा है।

The attitude of the Left towards India as a nation has been negative since the beginning. They never accepted that India is a sovereign nation. Due to this thinking, the Communists openly supported the divisive Lahore Resolution of the Muslim League in March 1940. Even today, by demanding independence for the states like Goa, Mizoram, Manipur, Kashmir and Kerala, the Left is furthering its anti-national agenda. In fact, the Left ideology has always been that of expansionism. It considers the feeling of nation and nationalism as the biggest obstacle in the way of its expansion. That is why they have a natural relationship with Islam and Christianity. That is why the Left has always tried to cover Islamic fanaticism in the veil of secularism. Today, when the life of almost the whole world and civilization is battling with jihadi mentality and religious terrorism, even then shameless efforts are being made by the leftists to fabricate arguments in their defense and mislead the common man.

मुख्य शब्द: भारत, भारत विभाजन और वामपंथ ।
Keywords: India, the Partition of India and the Left.

प्रस्तावना

देश इस वर्ष को अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रुप में मना रहा है। यह हम सभी के लिए अपने राष्ट्र से प्रेम करने और उस पर गर्व करने का एक शानदार अवसर है तो साथ ही एक ऐसा पड़ाव भी है जहां समय हमसे चीख-चीख कर यह पूछ रहा है कि क्या इसी खण्डित आजादी के लिए असंख्य शहीदों और देशभक्तों ने हंसते-हंसते मौत का आलिंगन किया था ? यही वह समय है जब इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए कि वह कौन सी विचारधारा के लोग थे जो आजादी मिलने से पहले ही भारत को खण्ड-खण्ड कर देना चाहते थे ? आखिर खण्डित और कमजोर भारत से उनके किस उद्देश्य की पूर्ति होने वाली थी ? भारतीय स्वतन्त्रता की इस अमृत बेला में भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों का गम्भीरता पूर्वक विश्लेषण करना राष्ट्र की एकता-अखण्डता और सुरक्षा की दृष्टि से भी नितान्त आवश्यक है।

यह सर्वविदित है कि एक राष्ट्र के रुप में भारत के प्रति वामपंथियों का दृष्टिकोंण प्रारम्भ से ही नकारात्मक रहा है। इन्होंने कभी यह स्वीकार ही नही किया कि भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र है। अपनी इसी सोच के कारण मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के विभाजनकारी लाहौर प्रस्ताव का कम्युनिस्टों ने खुलकर समर्थन किया था। आज भी गोआ, मिजोरम, मणिपुर, कश्मीर और केरल आदि राज्यों के लिए आजादी की मांग करके वामपंथी अपने राष्ट्र विरोधी एजेण्डे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तव में वामपंथी विचारधारा हमेशा से ही विस्तारवाद की रही है। यह अपने विस्तार के मार्ग में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना को सबसे बड़ी बाधा मानते है। इसीलिए इस्लाम और ईसाईयत से इनके स्वाभाविक रिश्ते बन जाते हैं। इसी कारण वामपंथियों ने हमेशा से ही इस्लामी धर्मान्धता को धर्मनिरपेक्षता के आवरण में ढकने का प्रयास किया है। आज जब लगभग समूचा संसार और सभ्यता का जीवन जेहादी मानसिकता और मजहबी आतंकवाद से जुझ रहा है तब भी इनके बचाव में तर्क गढ़ने और आमजनमानस को दिग्भ्रमित करने का निर्लज्ज प्रयास वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा है। स्वतन्त्रता संग्राम के समय जब सारा देश कांग्रेस की अगुआई में ब्रिटिश आधिपत्य से छुटकारा पाने के लिए आर-पार का संघर्ष कर रहा था उस समय वामपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग मुस्लिम लीग को कांग्रेस के विरुद्ध भड़काकर भारत को खण्ड-खण्ड करने की साजिश रचने में मशगूल थे। इन्होंने उन सभी अलगाववादी भावनाओं को उभारने का हर सम्भव यत्न किया जिससे भारत का अनेक हिस्से में बंटवारा हो जाय। इनकी रणनीति छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे भारत को आसानी से साम्यवादी प्रभाव के

अधीन कर लेने की थी। यद्यपि मुस्लिम लीग ने इस वामपंथी प्रस्ताव को खारिज करके उनके मंसूबो को विफल कर दिया था। 1946 में स्वतन्त्रता की सम्भावना पर विचार करने के लिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया तब उसके समक्ष वामपंथियों ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत को बाल्कन अथवा रुसी समाजवादी सोवियत संघ की ही तरह से सत्रह पृथक प्रभुसत्तापूर्ण राज्यों में बांट दिया जाय। वामपंथियों की यह राष्ट्रघाती मांग 1942 के उनके उस साम्यवादी प्रस्ताव के अनुरुप थी जिसमें यह घोषणा की गयी थी कि भारत एक बहु राष्ट्रवादी राज्य है और इसमें कम से कम कुल सोलह राज्य सम्मिलित हैं।[1]

साम्यवादी दर्शन के प्रणेता कार्ल मार्क्स भी भारत को एक राष्ट्र के रुप में मान्यता प्रदान करने के पक्षधर नहीं थे। उनका यह मानना था कि भारत की स्थिति एशिया में उसी प्रकार से है जैसे यूरोप में इटली की स्थिति है। यदि हिमालय को आल्पस, बंगाल के मैदान को लोम्बार्डी, दक्कन को एपेन्नीज और श्रीलंका को सिसली द्वीप के रुप में देखें तो उसकी कृषि तथा राजनीतिक संरचना में वही लक्षण विद्यमान है जिसका दर्शन हमें इटली में देखने को मिलता है। जिस तरह इटली में समय-समय पर आये आक्रान्ताओं ने अपनी ताकत के बल पर वहां के निवासियों को भिन्न-भिन्न जनसमूहों में विभाजित कर दिया था उसी प्रकार भारत भी मुस्लिम और ब्रिटिश आधिपत्य के पूर्व अनेक छोटे बड़े और प्रायः परस्पर विरोधी स्वतन्त्र निकायों में बंटा हुआ था जिसकी सत्ता नगरों अथवा गांवों तक ही सीमित होती थी। वस्तुतः भारत के बिषय में कार्ल मार्क्स की जानकारी का आधार यूरोपियन समाचार पत्रों में प्रकाशित वह टिप्पणीयां थी जो भारत और भारतीयता के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर लिखी गयी थी। जब वे भारत और उसकी सनातन परम्परा का माखौल उड़ाते हुए यह लिखते हैं कि यहां एक तरफ तो सर्वशक्तिमान जगन्नाथ की पूजा है तो वहीं दूसरी तरफ बिषयाशक्ति की प्रचुरता भी, एक तरफ सन्यासी हैं तो वहीं दूसरी ओर देवदासियों की भी व्यवस्था उपलब्ध है। भारतीय सनातन परम्परा के प्रति मार्क्स की यह कुत्सित दृष्टि और घृणित सोच से यह प्रमाणित है कि भारत और भारतीयता के प्रति उनकी समझ इधर-उधर से इकट्ठा की गयी ऐसी अधकचरी जानकारी पर आधारित थी जिसे औपनिवेशिक पूर्वाग्रह से प्ररित होकर तैयार किया गया था। लेनिन को लिखे एक पत्र में स्वयम् मार्क्स ने यह स्वीकार किया था कि उसे भारत के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। वह कभी भारत नहीं आये थे। न तो भारत और भारतीयता की उनको कोई समझ ही थी लेकिन यहां के लोगों के लिए उनकी सोच में भी अन्य यूरोपियनों की ही भांति घृणा और तिरस्कार के भाव को साफ-साफ देखा जा सकता है।[2]

भारत में वामपंथी विचारधारा से प्रभावित दलों ने भी अपने नायक की इसी मानसिकता से प्रेरणा ग्रहण करते हुए भारत को सत्रह टुकड़ों में बांट कर देखा तथा मुस्लिम लीग के पाकिस्तान निर्माण की मांग का पुरजोर समर्थन किया। यद्यपि सोवियत संघ में 1936 में लागू संविधान जिसे स्टालिन कांस्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें आत्मनिर्णय के अधिकार को तो मान्यता दी गयी थी लेकिन धार्मिक आधार पर विभाजन को सिरे से अस्वीकार कर दिया गया था। यही कारण है कि स्टालिन ने सोवियत संघ के यहूदियों के द्वारा धर्म के आधार पर अलग राज्य की मांग को नामंजूर कर दिया था।[3] लेकिन सोवियत संविधान और स्टालिन की इच्छा को अपने लिए पैगम्बर का आदेश मानने वाले वामपंथियों ने विशुद्ध धार्मिक आधार पर पाकिस्तान निर्माण के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का समर्थन करके अपने दोहरे चरित्र को ही उजागर किया। इनकी परस्पर विरोधाभासी कार्यशैली को देखकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित देश के अन्य प्रमुख नेताओं ने वामपंथी राजनीति के राष्ट्रघाती इरादों पर जमकर प्रहार किया था।

वामपंथियों के खतरनाक इरादों को देश के सामने बेनकाब करते हुए डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा यदि हम वाम दलों के द्वारा दी गयी राष्ट्र की परिभाषा को राष्ट्र निर्माण की कसौटी पर कसें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के सारे मुसलमान एक राष्ट्र नहीं कहे जा सकते हैं। वे सबके सब एक ही भाषा नहीं बोलते हैं। विभिन्न प्रान्तों और स्थानों पर उनकी भाषा अलग-अलग है। वास्तव मेंमुसलमान जिस प्रान्त में निवास करते हैं उसी प्रान्त की प्रान्तीय भाषा बोलते हैं। उनकी भाषा वही रहती है जो उस प्रान्त के गैर मुस्लिमों की भाषा होती है। पश्चिमोत्तर के लगभग चार प्रदेशों के मुसलमान अलग-अलग भाषा जैसे बलूची, सिंधी, पश्तो और पंजाबी बोलते हैं। ये भाषाएं एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न हैं जैसे कि हिन्दी, गुजराती और बंगाली एक दूसरे से भिन्न हैं। यह सच्चाई है कि जब तक हम सारे भारत को एक इकाई के रुप में मान्यता नहीं देगें तब तक यह तय करना कठिन होगा कि इसके सभी नागरिक एक ही राज्य में निवास करते हैं। भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग के मध्य जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है लगभग 1000 मील का फासला है। यहां हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानो का आर्थिक जीवन गैर मुस्लिम नागरिकों से अलग प्रकार का है। इसके विपरित सच्चाई यह है कि मुसलमान जिस प्रदेश में निवास करते हैं वहां के गैर मुस्लिम निवासियों की ही भांति उनका भी आर्थिक जीवन स्तर एक दूसरे से मिलता जुलता है। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने भारत में वामपंथियों के वैचारिक खोखलेपन को उजागर करते हुए कहा कि स्टालिन ने तो धर्म को किसी राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद मानने से साफ मना कर दिया था उल्टे अपने अनेक आलेखों और भाषणों के माध्यम से उसने धार्मिक आधार पर अलग स्वतन्त्र राष्ट्र के निर्माण की मांग का मजाक ही उड़ाया है।[4]

यद्यपि वामपंथी यह तर्क देते हैं कि स्टालिन के राष्ट्र निर्माण की परिभाषा में किसी सांस्कृतिक सम्प्रदाय में समाहित मनोवैज्ञानिक ढांचा धर्म के आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार देता है। राष्ट्र

निर्माण के इस वामपंथी कुतर्क को खारिज करते हुए डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इस्लाम में मुसलमान भी अन्य समुदायों की भांति अलग-अलग रंगों में रंगा हुआ ही दिखायी पड़ता है। शिया और सुन्नी का मतभेद व्यवहारतः उतना ही पुराना है जितना पुराना इस्लाम है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों में कितने ही ऐसे फिरके, दल और गुट हैं जो पहले हिन्दू थे और जो आज भी हिन्दू धर्म की अनेक रितियों, रिवाजों, प्रथाओं और परम्पराओं का पालन करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्र राष्ट्र के सन्दर्भ में स्टालिन द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार पाकिस्तान के निर्माण की मांग करना और ऐसी किसी भी मांग का समर्थन करना सर्वथा अनुचित है। वामपंथी राजनीति के पैरोकारों ने न केवल भारत विभाजन की मांग का समर्थन किया वरन् पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में अपनी पार्टी के अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित किया था। प्रख्यात वामपंथी समाजशास्त्री ए0 आर0 देसाई ने अपनी पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि में साफ तौर पर उस प्रस्ताव का उल्लेख किया है। जिसमें वामपंथियों ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हुए भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को जायज ठहराया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह लिखा है कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी अधिक है वहां उनके स्वायत्तशासी राज्य तथा भारत से पृथक होने के उनके नैसर्गिक अधिकार को वामपंथी स्वीकार करते हैं। इस सन्दर्भ में एक अन्य प्रमुख वामपंथी नेता डॉ0 जी0 अधिकारी ने कहा कि यदि हम पाकिस्तान की मांग के सारभूत तत्व का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में यह मांग पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों आदि की मुस्लिम राष्ट्रीय इकाईयों के आत्मनिर्णय और स्वतन्त्र हो सकने के अधिकार की औचित्यपूर्ण मांग है।

भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की मांग का समर्थन करना वामपंथी राजनीति के लिए कितना आत्मघाती साबित हुआ इसकी पुष्टि स्वयम् केरल के भू०पू० पू0 मुख्यमंत्री एवम् वरिष्ठ वामपंथी नेता ई0एम0 एस0 नम्बूदरीपाद के उस कथन से हो जाती है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आन्दोलन और जनयुद्ध के प्रश्नो के अतिरिक्त साम्राज्यवाद विरोधी आम भारतीय जनमानस से हमारे अलगाव का एक प्रमुख कारण मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान निर्माण की मांग का वामपंथियों द्वारा किया गया समर्थन था। पूंजीवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस और अलगाववादी साम्प्रदायिक मुस्लिम लीग को एक समान समझने की यह एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत भारतीय राजनीति में वामपंथियों को अभी आगे अनेक वर्षों तक चुकानी पड़ेगी।[5]

दरअसल वामपंथियों ने भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण के लिए मुस्लिम लीग की मांग का समर्थन इस विश्वास में किया था कि नवोदित पाकिस्तान में वामपंथी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना उनके लिए बहुत आसान रहेगा साथ ही भारत में निवास करने वाली शेष मुस्लिम आबादी में अपने लिए अपेक्षाकृत अधिक सम्मान और समर्थन जुटा सकेगें। वामपंथी राजनीति की यह एक अजीब खासियत है कि वह जनता को तभी तक शक्तिशाली होने देती है जब तक सत्ता पर उसका नियन्त्रण मजबूत होता है। शासन की बागडोर पर ज्योंहि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है तो जनता को कमजोर बनाये रखना ही उसे अपने राजनीतिक हित सिद्धि के लिए अनुकूल लगने लगता है। चूंकि भारत में वामपंथी राजनीति सत्ता के प्रभावशाली दावेदार के रुप में आज तक कभी भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पायी इसलिए सत्ता की मुख्य धारा से बहुत दूर वामपंथियों ने हमेशा से ही भारत और भारत की जनता को कमजोर करने का ही प्रयास किया है। वामपंथ के विस्तारवादी अन्तर्राष्ट्रीयतावादी विचार को सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रवादी विचारधारा से ही है। इसीलिए प्रख्यात समाजवादी विचारक डॉ0 राममनोहर लोहिया ने लिखा है कि सत्ता में नहीं रहने पर साम्यवाद मजबूत राष्ट्रवादी विचारधारा को अपना शत्रु मानने लगता है और उसे कमजोर करने लिए हमेशा विभाजनकारी तरीके अपनाता रहता है।[6]

यह उल्लेखनीय है कि वामपंथियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय हमेशा महात्मा गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने का असफल प्रयास किया। गांधी जी की अगुआई में चलने वाले राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को कैसे कमजोर किया जा सके इसका असफल प्रयास वामपंथियों ने प्राण-प्रण से किया था। वामपंथी विचारधारा के मुरीद बन चुके पं0 जवाहर लाल नेहरु ने यद्यपि गांधी जी के विचारों से समझौता करते हुए सत्ता तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के पश्चात राष्ट्रीय सत्ता के लोभ में वामपंथियों ने पं0 जवाहरलाल नेहरु की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति का बिगुल बजा दिया था। यदि समय रहते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सशक्त प्रतिरोध नही किया होता तो खूनी क्रान्ति के जरिये वामपंथी सम्भवतः राष्ट्र की सत्ता पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने में कामयाब हो जाते। सत्ता विरोधी इस षड़यन्त्र के विफल और बेनकाब होने के कारण तिलमिलाए वामपंथी भारतीय राजनीति में समझौता और संघर्ष की नीति का अनुसरण करते हुए निरन्तर देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करने की साजिश करते रहते हैं। इनकी दृष्टि में हर वह व्यक्ति, विचार, संस्था और सरकार फासीवादी है जो भारत को सशक्त बनाने के इरादे से कार्य करती है।

उद्देश्य

भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार वामपंथी दलों की भूमिका का शोध-परक विश्लेषण।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध.पत्र से यह स्पष्ट है कि वामपंथियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय हमेशा महात्मा गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने का असफल प्रयास किया। गांधी जी की अगुआई में चलने वाले राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को कैसे कमजोर किया जा सके इसका असफल प्रयास वामपंथियों ने प्राण-प्रण से किया था। वामपंथी विचारधारा के मुरीद बन चुके पं0 जवाहर लाल नेहरु ने यद्यपि गांधी जी के विचारों से समझौता करते हुए सत्ता तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के पश्चात राष्ट्रीय सत्ता के लोभ में वामपंथियों ने पं0 जवाहरलाल नेहरु की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति का बिगुल बजा दिया था। यदि समय रहते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सशक्त प्रतिरोध नही किया होता तो खूनी क्रान्ति के जरिये वामपंथी सम्भवतः राष्ट्र की सत्ता पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने में कामयाब हो जाते। सत्ता विरोधी इस षड़यन्त्र के विफल और बेनकाब होने के कारण तिलमिलाए वामपंथी भारतीय राजनीति में समझौता और संघर्ष की नीति का अनुसरण करते हुए निरन्तर देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करने की साजिश करते रहते हैं। इनकी दृष्टि में हर वह व्यक्ति, विचार, संस्था और सरकार फासीवादी है जो भारत को सशक्त बनाने के इरादे से कार्य करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *ग्रोवर बी०एल० एवम् यशपालः आधुनिक भारत का इतिहास, एस०चन्द एण्ड कं०, दिल्ली-2000.*
2. *देव,संदीप : कहानी कम्युनिस्टों की, ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन,नई दिल्ली-2017.*
3. *स्टालिन, जोसेफ : मार्कसिज्म एण्ड द नेशनल एण्ड कालोनियल क्वेश्चन, कोआपरेटिव पब्लिशिंग सोसायटी आफ फारेन वर्क्स इन द यू०एस०एस०आर०-1935 .*
4. *प्रसाद,राजेन्द्र : खण्डित भारत, प्रभात प्रकाशन,नई दिल्ली-2009.*
5. *नम्बूदरीपाद, ई०एम०एस० : एक भारतीय कम्युनिस्ट की स्मृतियां,ग्रन्थ शिल्पी-नई दिल्ली 2013.*
6. *लोहिया,राममनोहर : भारत विभाजन के गुनहगार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-2008.*